

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1633

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

स्वच्छ नदी स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना

1633. श्री दामोदर अग्रवाल:

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्री तापिर गावः

श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्री अनन्त नायकः

श्री विजय बघेलः

श्री शंकर लालवानीः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत वाराणसी में वरुणा नदी पर एक स्वच्छ नदी स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) स्थापित की है और यदि हां, तो उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) इससे नदियों के कायाकल्प और प्रबंधन में सुधार लाने में किस प्रकार मदद मिलेगी और वरुणा नदी की चुनौतियों के समाधान के लिए एसएलसीआर द्वारा अपनाए गए स्थायी उपाए क्या हैं;
- (ग) उक्त परियोजना के लिए भारत और डेनमार्क सरकार द्वारा आनुपातिक आधार पर किस प्रकार धन उपलब्ध कराया जाएगा;
- (घ) क्या सरकार देश के अन्य हिस्सों की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें उक्त परियोजना के दायरे में लाने के लिए विचार कर रही हैं;

- (ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र और ओडिशा के क्योंझर जिले सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या सरकार की महाराष्ट्र सहित देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे एसएलसीआर स्थापित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): स्वच्छ नदी स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत की गई है, ताकि स्वच्छ नदी जल के क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों के संबंध में वैश्विक स्तर पर समाधान हासिल किए जा सकें और इनका लिविंग लैब एस्टिकोण के माध्यम से वास्तविक वातावरण में फिट होने के लिए सहयोगी अनुसंधान और विकास का कार्य किया जा सके और सरकारी प्राधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच स्वच्छ नदी जल प्राप्त करने के लिए ज्ञान साझा करने और सह-निर्माण के लिए एक मंच सृजित किया जा सके।

(ग): भारत सरकार ने स्वच्छ नदी स्मार्ट प्रयोगशाला के सचिवालय की प्रचालन लागत 10 वर्षों के लिए स्वीकृत की है और तीन परियोजनाओं की लागत भी स्वीकृत की है। डेनमार्क ने इस पहल के लिए चार मिलियन डेनिश क्रोन की धनराशि आवंटित की है।

(घ), (ङ) और (च): जी, नहीं।
